ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु कुछ सुझाव

CMA बी. एल. गुर्जर
239 महादेव नगर, जगतपुरा,
जयपुर, राजस्थान

1. परम आदरणीय अटल बिहारी जी की नदियों को जोडने की योजना पर विचार क्यों नहीं हो रहा है। एक तरफ नदियों में बाढ से देश के कुछ भू–भागों में प्रति वर्ष भयंकर तबाही हो रही है एवं अमृत तुल्य पानी समुद्र में व्यर्थ बहकर चला जाता है। दूसरी ओर राजस्थान सहित देश के बहुत से भू–भागों में दसों वर्षों से सूखा पड रहा है । परिणाम स्वरूप लाखों एकड जमीन पानी के अभाव में बंजड हो गई है एवं लाखों किसान मजदूर परिवार बेरोजगार होकर दाने दाने को मोहताज हो गये हैं। इस योजना पर यदि काम हो तो पूरे देश में खुशहाली आयेगी तथा बाढ एवं सूखा दोनों से राहत मिलेगी। लाखों किसान परिवारों की तकदीर ही बदल जायेगी।

2. प्रगति एवं विकास के लिए लोग नेताओ को कोसते हैं। वास्तविकता में राजनेता सत्ता संचालन के लिए आई0ए0एस0 जैसी सिविल सर्विसेज के ब्यूरोक्रेट्स (अफसरों) पर निर्भर होते है। शिक्षा, कृषि, वाणिज्य, विज्ञान एवं तकनीकी, लेखा, राजस्व, कर, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, शहरी विकास, ग्रामीण विकास आदि सभी क्षेत्रों की नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका ब्यूरोक्रेट्स की ही होती है। वे देश के वास्तविक भाग्य विधाता हैं।

मजे की बात यह है कि सिविल सर्विसेज में प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया अंग्रेजो के जमाने से करीब करीब ज्यो की त्यों चली आ रही है। किसी भी विषय में स्नातक कोई भी व्यक्ति इन परीक्षाओं के माध्यम से अपना चयन करवा सकता है एवं मेरिट के आधार पर शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखे बिना उसे कोई भी सेवा जैसे प्रशासनिक सेवा, राजस्व सेवा (जीएसटी), लेखा सेवा, आदि एलाट हो जाती है। अब कल्पना करिये एक व्यक्ति जो दर्शन शास्त्र या समाज शास्त्र में स्नातक है एवं ये ही वैकल्पिक विषय लेकर सिविल सेवा में चयन होकर उसे राजस्व सेवा या लेखा सेवा एलाट हो जाती है तो आप खुद समझ सकते हैं उस विभाग की क्या हालत होगी। क्या होता होगा जब राजस्व सेवा का एक अधिकारी जो मानविकी संकाय से स्नात्तक/स्नातकोत्तर है और वह एक चार्टेड अकांउटेट के खातो की जांच कर टैक्स निर्धारित करता है।

कोई भी सरकारी विभाग चाहे वह वित्त विभाग हो या परमाणु उर्जा विभाग हो एक निश्चित रूप उसका विभागाध्यक्ष एक आई0ए0एस0 अधिकारी ही होगा चाहे वह इन विभागों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता रखता है या नहीं।

आजादी के बाद देश की शिक्षा का स्तर कई गुना बढा है। सब तरह की सेवाओं यथा वाणिज्य, लेखा, विज्ञान, तकनीकी आदि के लिए प्रचुर मात्रा में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। फिर क्यों नहीं सरकार सिविल सर्विसेज का रिव्यू कर अलग अलग विभागों के लिए संबंधित शैक्षणिक/प्रोफेशनल योग्यताएं रखने वाले व्यक्तियों को शामिल करते हुए अलग अलग प्रतियोगी परीक्षएं आयोजित करें एवं उन्हें पूरी सर्विस के दौरान उसी विभाग में रखा जाए। ग्रामीण विकास से संबंधित विभागों में प्रतियोगियों का ग्रामीण बैक–ग्राउण्ड भी होना चाहिए ताकि सरकारी योजनाए सही रूप से बने एवं सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके।

3. अन्य राष्ट्रों की तरह हमारे देश में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों नहीं मिलती। क्यों नहीं देश का सर्वोत्तम टेलेंट इस क्षेत्र में आता है। सरकारी क्षेत्र के स्कूल, कॉलेजों का स्तर क्यों लगातार गिरता जा रहा है। जन सामान्य और गरीब व्यक्ति तो अपने बच्चों को सरकारी क्षेत्र के स्कूल, कॉलेजों में ही पढा पाते हैं। गांवों में शिक्षा के हालात और बदतर हैं।

इसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दिया जाना है। सरकार द्वारा शिक्षक को केवल शिक्षा के प्रति ही समर्पित क्यों नहीं रहने दिया जाता। जनगणना हो या पशुगणना, वैक्सीनेशन हो या टीकाकरण, मतदाता सूचियों का अपडेसन हो या सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, सभी कुछ शिक्षकों के जिम्मे डाल दिया जाता है। चुनाव की तो पूरी प्रक्रिया ही शिक्षकों के जिम्मे डाल होती है। फिर शिक्षक छात्रों को पढाने के लिए समय कब निकालेगा। और तो और चुनावों में तो स्कूल और कॉलेजों के भवन मतदान की तैयारी और मतगणना के लिए महीनों तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हथिया लिये जाते हैं। छात्रों की महीनों तक छुट्टियां हो जाती हैं। पाठ्यक्रम पूरा हो या न हो परीक्षा तो निर्धारित समय पर करानी ही होती हैं। फलस्वरूप आधी अधूरी पढाई से ही छात्रों को परीक्षा देनी होती हैं। इसलिए कुछ छात्र नकल आदि गैर कानूनी माध्यमों का सहारा लेते है या प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की शरण लेते हैं। सुझाव यह है कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्यालय /महाविद्यालयों में पूर्णकालिक केवल शैक्षणिक गतिविधियां हो एवं गुणवत्ता में सुधार किया जाए, ताकि निर्धन वर्ग के बच्चे भी आगे बढ कर देश की प्रगति में योगदान कर सकें।

4. वर्तमान में सबसे अधिक खराब हालत महाविद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी उच्च शिक्षा की है। उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों की संख्या कई गुना बढ गई है, किन्तु गुणवत्ता बहुत नीचे आ गई है। बडी संख्या में प्राईवेट संस्थान भी केवल डिग्री बांटने के केन्द्र बन गये हैं। तकनीकी शिक्षा हो या कला, वाणिज्य आदि शिक्षा सब बेहाल हैं। पाठ्यक्रम में बडी बडी किताबें हैं, किन्तु सामान्य छात्र ईमानदारी से पाठ्यक्रम का कुछ प्रतिशत भी नहीं समझते, फिर भी अच्छे नम्बरों से पास हो रहे हैं। देश और खासकर गरीब बच्चों को बचाना है तो उच्च शिक्षा क्षेत्र में आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। क्या कोई सिस्टम ऐसा नहीं बन सकता कि शिक्षक एवं छात्र एक भी क्लाश नहीं छोडे। क्या सिलेबस को अधिक व्यावहारिक बनाकर ऐसा नहीं करें कि शिक्षक उसे शिक्षा सत्र में ईमानदारी के साथ पूरा कर सकें। क्या प्रश्न पत्र में प्रत्येक

अध्याय में से कुछ न कुछ पूछा जाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रस्तिकाओं का मूल्यांकन क्या पूरी ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पाइंटस क्या नियमित अध्ययन के सिलेबस में शामिल नहीं हो सकते। उपरोक्त हर प्रश्न का उत्तर हरेक व्यक्ति हॉ में ही देगा। फिर काहे की देरी। कर्ता–धर्ता इसे तुरंत लागू क्यों नहीं करते। सिर्फ इच्छा शक्ति के कारण ! वह केवल जन सामान्य के जागरूक होने पर ही संभव है।

वर्तमान सरकार सहित पिछली प्रत्येक सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, फिर भी बेराजगारी ने विकराल रूप धारण कर रखा हैं। लाखों करोडों रूपये की महानरेगा योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए है, क्या उसे अधिक व्यावहारिक नहीं बनाया जा सकता। यह काम पब्लिकम प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर आसानी से किया जा सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय मेहनत करने में नम्बर वन हैं। किन्तु मेहनत करने का मौका तो मिले। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तो अगर पैसा मिले तो रात और दिन काम करने को तैयार हैं। इसके लिए सरकार को भौगोलिक परिस्थितियों एवं उपलब्ध स्त्रोतों के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। बहुत साधारण बात है– गांव के लोगों को कच्चा माल /पार्टस दीजिये , मात्रा के आधार पर जॉब वर्क का भुगतान कीजिए एवं तैयार माल की गुणवत्ता की जांच कर वापिस लीजिए। फिर देखिये गांवों की उत्पादकता । पूरी दुनिया में भारत का माल छा जायेगा । इसके लिए महानरेगा के फंड का भी बखूबी इस्तेमाल हो सकता है एवं कारपोरेट सेक्टर भी इसमें नियमानुसार योगदान कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। महोदय जरा सोचिये तो सही।

5. एक अंतिम बात गोरक्षा के संबंध में । आम भारतीय गाय को गोमाता ही मानता है, इसके लिए कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं है। गो–संवर्धन की बात करनी है तो एसी रूम से निकल कर किसानों एवं गोपालकों से बात करिये। महोदय गाय की किस्म सुधारिये। भारत में अधिकांश गाये प्रतिदिन 2–3 किलो दूध साल में 3–4 महीनें ही देती है। अधिकांश समय गोपालक को व्यर्थ में ही उसे चारा खिलाना पडता है। दुनिया के कई देशों में गांये 30–40 किलों दूध प्रतिदिन वर्ष पर्यन्त देती है साथ ही गाय के अपशिष्ट गोबर एवं मूत्र भी औषधि एवं रेडियोधर्मिता आदि में काम आते हैं। क्या सरकार गाय की नस्ल सुधारने एवं इसके विभिन्न उत्पादों को उपयोगी बनाकर गाय को किसान के लिए आर्थिक रूप से अधिक उपयोगी नहीं बना सकती ? फिर देखिये वास्तविक गोसंवर्धन होता है कि नहीं !

****